फा. सं. 9-1/2017-एफईएस-ई.एस.
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(खाघान्न अर्थशास्त्र अनुभाग)

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 06 फरवरी, 2018

श्री मोहित सिंह ,
332, पाना मोहमदपुर,
निन्दा(107),
रोहतक - 124513
हरीयाणा

विषय: **जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, पंजीकरण संख्या DOA&C/R/2017/02044 के तहत श्री मोहित सिंह द्वारा कुल उत्पादन तथा विभिन्न राज्यों में फसलों के उत्पादन सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।**

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर अपने दिनांक 19.12.2017 के पत्र का अवलोकन करें।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सरकार कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने तथा उत्पादन बढाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान मे रखकर प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्णय लेती है, जिससे कृषकों को अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त हो सकें। फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय सीएसीपी उत्पादन लागत, बाजार मूल्यों में प्रवर्तियां, मांग एवम आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव तथा जीवन लगत पर प्रभाव को सम्मिलित करती है।

सरकार ने 2016-17 तथा 2017-18 के लिए खरीफ और रबी फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उसके पिछले वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त दलहनों तथा तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा बोनस की घोषणा भी की गई है।

फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक पहलें की हैं जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय दोगुना करने के लिए नीति बनाने हेतु एक समिति का गठन करना शामिल हैं।

सरकार द्वारा अन्य प्रयासों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा प्रोत्साहन बोनस प्रदान करने से फसलों के उत्पादन पर वांछित प्रभाव पड़ा है। 2016-17 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यानों का कुल उत्पादन 275.68 मिलियन टन अनुमानित है जो कि 2015-16 के 251.57 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 24.11 मिलियन टन अधिक है।

पुनीत कुमार
(पुनीत कुमार)
सहायक निदेशक